उत्तराखंड उच्च न्यायालय
25 जनवरी, 2021 को परमजीत सिंह सागर बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य
(निर्णय सुरक्षित)

उत्तराखंड के उच्च न्यायालय, नैनीताल में

2019 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 269

परमजीत सिंह सागर .....संशोधनवादी

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

वर्तमान: श्री वीके कोहली, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री कांति राम शर्मा द्वारा सहायता प्राप्त,
आवेदकों के लिए वकील.
श्री सुभाष त्यागी भारद्वाज, उप. सुश्री शिवांगी गंगवार के साथ एजी, संक्षिप्त
राज्य के लिए धारक.
श्री राकेश थपलियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ललित शर्मा द्वारा सहायता प्रदान की गई।
निजी प्रतिवादी के लिए वकील।

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण विवेचक/पति द्वारा 2017 के केस संख्या 426 "श्रीमती नीतू बनाम परमजीत" में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, देहरादून द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 06.04.2019 के fo:} दायर किया गया है, जिसके तहत निचली अदालत ने पुनरीक्षणकर्ता/पति को रुपये का अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया है। 18,000/- (केवल अठारह हजार रुपये) पत्नी और बेटे यानी प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 को।

2. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और पक्षों की वित्तीय स्थिति पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अंतरिम भरण-पोषण देने के लिए इस स्तर पर मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है।

3. प्रतिवादी संख्या द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है। 2 और 3 जिसमें विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, देहरादून ने प्रतिवादी संख्या के पक्ष में अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया है। 2 और 3. हालाँकि, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने पक्षों के बीच सुलह के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। इस प्रकार, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, देहरादून को निर्देश दिया जाता है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन पर फैसला देने से पहले , वह पक्षों के बीच सुलह का प्रयास करेंगे।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. इसके मद्देनजर, पार्टियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन पर कानून के अनुसार फैसला करने के प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, देहरादून को निर्देश के साथ आपराधिक पुनरीक्षण का निपटारा किया जाता है।

(लोकपाल सिंह, जे.)
25.01.2021